बात सरकार सोचेगी और इस देश में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर्स बनायेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके ?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस देश में 4 हजार की कीमत का ट्रैक्टर 15-16 हजार में बिक रहा है और किसानों की खाल उतारी जा रही है इसलिए क्या सरकार इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई ऐसी ऐजेन्सी निकालेगी जिसके जरिये से ट्रैक्टर्स सही कीमत पर किसानों को मिल सकें ?

SHRI RAGHUNATH REDDI : Government have already decided on various priorities, and certainly luxury goods will never get any priority in the hands of Government and tractors would certainly be given the highest priority.

Regarding the second question which the hon. Member has put namely whether a tractor costing about Rs. 4000 is sold for about Rs. 15000 or Rs. 16000, I would like point out that the selling price of tractors is as follows :

26.5 H.P.	Rs. 17.836
35 H.P.	Rs. 20,900
35 H.P.	Rs. 20,838
34.5 H.P.	Rs. 19,500
28.0 H.P.	Rs. 15,032
50 H.P,	Rs. 21,880
35 H,P. (Hindustan Tractors and Bull-dozers Ltd.)	Rs. 16, 110

Therefore, I do not know how the hon. Member has got this impression that a tractor costing Rs. 4000 is sold for about Rs. 16000.

श्री ओंकार लाल बेरवा : अभी अभी कोई 15 दिन पहले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री सुखाड़िया जी ने कहा है कि कोटा ट्रैक्टर्स का कारखाना खोला जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है, मन्त्री जी को इसका पता है ?

SHRI RAGHUNATH REDDI : I am not aware of it.

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या यह बोगस बात ही है ?

MR. SPEAKER : He has said that he is not aware of it.

बात सही हो सकती है लेकिन मन्त्री जी को इसका पता नहीं है ।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Motor trucks are available on a hire-purchase basis. May I know whether there is any scheme with Government to make available the tractors on a hire-purchase system to the farmers ?

SHRI RAGHUNATH REDDI : Government have no hire-purchase system at their disposal. There are various financial organisations which would look into it.

SHRI K. LAKKAPPA : The hon. Minister has stated that the manufacture of small tractors for agriculturists can be done at the instance of Government either by private concerns or by the public sector. Since it is the policy of Government to permit manufacture of small tractors either under the private sector or under the public sector, may I know whether Government would give a categorical assurance to the House that they would not issu any licences to the blacklisted capitalists and industrialists in this country who are under a cloud?

SHRI RAGHUNATH REDDI : While Government are anxious to have tractor manufacture in the public sector, as I have already stated, there is no prohibition on private industry starting tractor manufacture, in view of the huge demand that is being projected in relation to the necessity of tractors for agriculturists.

SHAI K. LAKKAPPA : My question was wnether licences would be refused for blacklisted industrialists.

SHRI RAGHUNATH REDDI : If any blacklisted industrialists applies for a licence, certainly the question would be considered on merits, and as long as his name is on the black list, it would not be considered.

कपास के मूल्य

*1230. **श्री देवराव पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के मूल्यों की न्यूनतम और

अधिकतम सीमाएं समाप्त किये जाने के बाद खुले बाजार में प्रत्येक राज्य में नवम्बर-दिसम्बर 1967 में कपास का मूल्य क्या था और इस समय वह मूल्य क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि कपास के वर्तमान मूल्य उत्पादकों के लिये लाभकर है ; और

(ग) यदि हां, तो कपास उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने तथा आगामी मौसम में कपास के उत्पादन में कोई कमी न होने देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT—897/68.]

श्री देवराव पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैंने लोक-सभा के इसी सत्र में कपास के बारे में कई मर्तबा सवाल पूछे हैं लेकिन यह वाणिज्य मन्त्री महोदय रूई और कपास में कोई फर्क नहीं जानते हैं। कौटन किस को कहते हैं और रा कौटन किस को कहते हैं इसे वह समझते ही नहीं हैं...

MR. SPEAKER: The hon. Member may come to the question please.

श्री देवराव पाटिल : मेरा क्वैश्चन रा कौटन के बारे में है और कपास के उत्पादन के लिए जो प्राइस दी गई है उस के बारे में मेरा सवाल है जबकि मिनिस्टर महोदय ने जो विवरण दिया है वह रूई के बारे में दिया है। यहां पर मिनिस्टर ने जो रूई के बारे में स्टेटमेंट दिया वह ग़लत दिया है क्योंकि मेरा क्वैश्चन कपास के बारे में है। और कपास उत्पादकों को उस की प्राइस देने के बारे में है जबकि मिनिस्टर ने जो उत्तर दिया है वह रूई के बारे में दिया है। ट्रेडर्स जो रूई कपड़ा मिलों को बेचते हैं उस के बारे में दिया है।

गये साल जब कपास का उत्पादन देश में बहुत कम था तो कपड़ा मिल मालिकों ने सरकार को नोटिस दिया था कि हम मिलें बन्द करेंगे। सरकार ने यानी कामर्स मिनिस्टरी ने ऐसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट में संशोधन करके किसानों की कपास जबरदस्ती ले ली थी। इस साल देश में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा है और मिल मालिकों ने फैसला किया है और रेजौलूशन पास किया है एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं बल्कि तीन दफ़े रेजौलुशन पास किया है कि हम किसान की कपास एक महीने से ज्यादा नहीं लेंगे। किसान की कपास नवम्बर से अप्रैल तक यानी 6 महीने में मार्केट में आ जाती है और मिल मालिक सिर्फ एक महीने की कपास लेना चाहते हैं, यानी 6 महीने की कपास लेना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी जो 6 महीने की कपास बाज़ार में पड़ी रहेगी, आज बाज़ार में कपास लेने को कोई तैयार नहीं। मैं आप की मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसान को उचित मूल्य देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने रूई और कपास का फर्क बिलकुल ठीक बतलाया है। रूई और कपास का फर्क उन को भी मालूम है और मुझ को भी मालूम है। हम दोनों ने उस की बातें भी की हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी आप ने उन का जो लम्बा बयान था सवाल के रूप में उस को सुना और उस में उन्होंने कहा कि मिल मालिक जो कपास खरीदते हैं, वह भी जानते हैं कि कपास मिल मालिक नहीं खरीदते हैं, वह तो रूई खरीदते हैं लेकिन वह जो कपास और रूई को कहते हैं तो हम ने समझा कि उस की कीमत वह जानना चाहते हैं इसलिए मैंने इस चीज़ को उन के सामने रक्खा था...

श्री महाराज सिंह भारती : रूई के मिल मालिकों को किसान कपास बेचते हैं और कपड़े के मिल मालिकों को रूई वाले रूई बेचते हैं।

श्री दिनेश सिंह : यह एक नई बात भी

गई लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल किया वह एक अहम सवाल है। उस को मैं ने जब मेरे मन्त्रालय के खर्च के बारे में यहाँ पर बहस हुई थी उस में मैं ने बतलाने की पूरी कोशिश की थी कि हम कोशिश करेंगे कि एक उचित मूल्य किसान को उस की कपास का मिलना चाहिए मैं ने अपने जवाब में कहा था कि एग्रीकलचरल प्राइस कमिशन इस पर जांच करेगा और उस के हिसाब से हम उसकी न्यूनतम कीमत रक्खेंगे।

श्री देवराव पाटिल : दूसरा मेरा सवाल यह है कि कृषि की जो, जो चीजें हैं उन के बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने निर्धारित की है जैसे कि गेहूँ, ज्वार या राइस के बारे में सपोर्ट प्राइस निर्धारित की है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों से आज तक जो कपास रैगुलर मार्केट में किसानों से खरीदी जा रही है उस के लिए अभी तक कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं फिक्स की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई है।

श्री देवराव पाटिल : क्या रा कौटन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं वह रूई के लिए है।

श्री देवराव पाटिल : मेरा सवाल था कि इन 25 सालों में वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर क्यों नहीं निर्धारित की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य का ध्यान मैं पिछले सैशन की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें बतलाया गया था कि 20 साल से रूई के ऊपर एक नियन्त्रण रहा है और उस के हिसाब से रूई की कीमतें बढ़ती गई हैं और रुई के ऊपर जो नियन्त्रण था उस कीमत के हिसाब से वह यहां बिक रही थी। माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने यह कहा कि इस पर से नियन्त्रण हटा दिया जाय तो हम ने उसी वक्त उन को यह चेतावनी दी थी कि आप इस के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाले हैं लेकिन उस वक्त उन्होंने हमारी इस चेतावनी का ख़याल नही किया। माननीय सदस्य वह रूई और कपास की जितनी बातें कर रहे हैं तो उनमें बीज के ही दाम का फर्क है। दोनों एक दूसरे से मिली हुई चीज है बाक़ी हम फिर इस बात को दुहराना चाहते हैं कि हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जो किसान हैं उन को उचित मूल्य मिलें।

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: Would you please ask the Commerce Minister to correct both the question and his answer, because the original question speaks of prices of raw cotton prevalent in the respective States, and answer given is: veriety of cotton, State where mostly grown, Market price average in Nov-Dec. 1967! Now here has it been stated that these prices were prevalent in which State. Whether it is in the States of India or of the USA; even that has not been clarified.

Further, I am glad that the Minister knows that there is a difference between raw cotton and ginned cotton. How long is he going to take to know this simple fact that from Indian farms cotton does not come in the form of ginned and pressed bales and the price support which is expected for agricultural commodities has to be in the form of support for the form of cotton that is sold by the agriculturists? Luckily, raw cotton has a regular market and prices are announced everyday by Government's machinery, *viz.* AIR. And yet such simple questions are not answered. What steps do you, as Speaker, propose to take to see that questions which are being asked are answered and information asked for is supplied?

SHRI UMANATH: You have to reply to this.

SHRI S. K. TAPURIAH: The hon. Member can take steps by removing him.

SHRI DINESH SINGH: I can make your task easier by requesting him to read the question and the answer as it is printed.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: In the original question in Hindi the word used is *kapas*.

MR. SPEAKER: We cannot hold classes here on raw cotton and all that. Unfortunately, this is question hour.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: It is your job to see that the answers given are to questions asked.

MR. SPEAKER : Even the speaker cannot hold classes here.

SHRI S. C. SAMANTA : Is it not a fact that the Indian Central Cotton Committee recommended that minimum prices for raw cotton should be fixed? Have Government considered that recommendation and taken any steps?

SHRI DINESH SINGH : So far we have been thinking about support price for cotton, not raw cotton, as the hon. Member has said, because there is seperate sale of the cotton seed from the ginning stage onwards. It is very much easier to control the price of cotton. That is why there has been no consideration given so far to price control or support price of the product as it comes out from the farm, but only after ginning.

SHRI A. V. PATIL : It is a matter of regret that the question of cotton prices is not being handled properly. The result is that the poor farmer is suffering for the last so many years. He has to work under two in-laws, one the Agriculture Ministry and the other the Commerce Ministry, one very kind and the other very unkind. When he has produce to the cotton, the Agriculture Ministry tries to help him, but on the price question, the Commerce Ministry does not help him. The reason is that the whole policy of the Commerce Ministry is oriented to safeguard the interests of the textile industry and not the interests of the farmer. In view of this fact, may I know whether Government's policy will be reconsidered and made farmer-oriented rather than millowner-oriented?

SHRI DINESH SINGH : I strongly repudiate the charge made by the hon. member. There is no discrimination against the farmer. He is quite wrong in the statement that he has made. In fact, he knows very well that whatever the recommendation of the Price Commission was in regard to agricultural commodities, the prices which were fixed were higher.

SHRI UMANATH : Some time back many of the mills had to close or threatened closure due to the cotton crisis, partly due to the so-called reason of non-availability and partly due to cornering of stocks by speculators. Taking a lesson from that and in order to avert such a thing repeating itself, I would like to know from the Government what is the reason for Government not entering the market and purchasing from the growers straight at a reasonable price and stocking the cotton so that such cornering does not take place. Secondly, forward trading in cotton has not been totally banned though it has been repeatedly convassed on the floor of the House. I would like to know why the Government hesistates to totally ban forward trading in cotton.

SHRI DINESH SINGH : I do not know whether my hon. friend is a cotton farmer, but he will appreciate that that if we can forward trading in cotton, the prices, if anything, are likely to come down, and I do not think that the cotton growers will support him in asking for banning of forward trading. What we banned is hedge which is speculation in cotton.

As for the other question, under your direction we utilise the Question Hour for giving information and not discussing policy. That is a larger policy issue.

SHRI UMANATH : I am only eliciting information. I am asking for the reason why Government is not entering the market. He should tell the reason.

SHRI DINESH SINGH : I am giving the general reason that Government have not considered it necessary to enter into this field yet.

'पंट्रियट' और 'लिंक' के प्रकाशनों द्वारा रूस से छपाई की मशीन का आयात

+

*1231. **श्री भारत सिंह चौहान :**